



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 1 मई, 2003/11 वंशाख, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अप्रैल, 2003

संख्या एस0टी0ई0-ई0(4)-1/2003.—माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने याचिका संख्या 228/2002-नामतः देश राज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य में तारीख 3-3-2003 को पारित अन्तरिम आदेश द्वारा राज्य सरकार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रयोजनों और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त दिशा निर्देश विरचित करने के निर्देश दिए गए हैं ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और तदधीन बनाए नियमों के अधीन पर्यावरण अवक्रामण को रोकने और यातायात और मानव स्वास्थ्य के प्रति जोखिम से बचने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य में, पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाएं;

और भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 152 (ई), तारीख 10-2-1988 द्वारा अपनी शक्तियों उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन राज्य सरकार को प्रत्यायातित की है;

और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्टोन क्रशिंग इकाइयां वायु प्रदूषण, यातायात और मानव स्वास्थ्य के प्रति जोखिम उत्पन्न कर रही है ।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 152 (ई), तारीख 10-2-1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 और माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा सी० डब्ल्यू० पी० नम्बर 228/2002, तारीख 3-3-2003 के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राज्य के पर्यावरण और पारिस्थिकी को बचाने हेतु स्टोन क्रशिंग आपरेशनज पर बृहत्तर नियन्त्रण और निगरानी रखने के लिए एतद्वारा समस्त स्टोन क्रशिंग इकाइयां (जिन्हें इसके पश्चात् इकाई कहा गया है) के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश/निर्देश तुरन्त प्रभाव से अधिसूचित करते हैं :—

## 1. स्थल औचित्य :

### 1.1 मान (नार्मज) :

पहाड़ी स्थलाकृति भूमि की अल्प उपलब्धता और पहाड़ियों की कमजोर परिस्थिति के रख-रखाव की आवश्यकता को विचार में रखते हुए, इकाईयों का गठन, निम्नलिखित स्थान निर्धारण कसौटी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, अर्थात् :—

क्रम संख्या	कसौटी	दूरी
1.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग से/नजदीकी राज्य उच्च मार्ग से न्यूनतम दूरी	100 मी०
2.	जिला मुख्यालय से दूरी	1.5 कि० मी०
3.	किसी शहर/अधिसूचित क्षेत्र समिति से न्यूनतम दूरी	1.00 कि० मी०
4.	ग्रामीण आवादी देह न्यूनतम से दूरी	250 मी०
5.	अस्पताल या शिक्षा संस्थान से न्यूनतम दूरी	1.00 कि० मी०
6.	झरनों, नहरों, रेजर्वायरज और कार्यशील जल प्रदाय स्कीमों से न्यूनतम दूरी	100 मी०
7.	अधिसूचित झीलों और आद्र भूमियों (वेट लैंड) से न्यूनतम दूरी	500 मी०

## 1.2. टिप्पण :

- 1.2.1 सभी दूरियां शहर के कन्वेयर बेल्ट के उच्चतम शिरो बिन्दु से राजस्व इकाई या नगरपालिका सीमाओं की वाह्य परिधि या सम्बन्धित फीचर की परिधि तक सीधी लाईनों के रूप में मापी जाएगी ।
- 1.2.2 दिशा-निर्देशों में उपदर्शित किसी भी फीचर तथा इकाई के स्थल के मध्य किसी भी प्रकार का प्राकृतिक अवरोध होने की दशा में दिशा-निर्देश दूरियां शिथिल करने योग्य है ।
- 1.2.3 शिमला शहर की वास्तव स्थान निर्धारण मान (नार्मज) सी० डब्ल्यू० पी० संख्या 1993 की 51 तारीख 26-7-1993 नामतः "कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य" में, दिए गए माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के निर्देशों के अनुसार होंगे ।

1.3 स्थल मूल्यांकन के लिए संयुक्त निरीक्षण समिति—

1.3.1 इकाई अन्य सरकारी विभागों से पूर्व उत्पादन निर्वाहन अभिप्राप्त करने हेतु अस्थाई रजिस्ट्रीकरण के लिए उद्योग विभाग को आवेदन करेगी/इसे अभिप्राप्त करेगी।

1.3.2 इकाई की स्थापना के लिए स्थल का मूल्यांकन और अनुमोदन निम्नलिखित से गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:—

- |    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | सम्बन्धित उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)   | अध्यक्ष     |
| 2. | वन-मण्डल अधिकारी (डी० एफ० ओ०) या उसका प्रतिनिधि                               | सदस्य       |
| 3. | हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रतिनिधि | सदस्य       |
| 4. | लोक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियन्ता या उसका प्रतिनिधि                       | सदस्य       |
| 5. | सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का अधिशासी अभियन्ता या उसका प्रतिनिधि            | सदस्य       |
| 6. | पर्यटन विभाग का प्रतिनिधि   | सदस्य       |
| 7. | भू-विज्ञानी या खनन अधिकारी  | सदस्य-सचिव। |

1.3.3 पैरा 1.3.2 में गठित समिति उद्योग विभाग की अधिनूयता संख्या उद्योग-1 (छ) 4-1/85-II तारीख 26-4-93 और 24-12-1998 के अधिक्रमण में है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, और उद्योग विभाग द्वारा स्थाई रजिस्ट्रीकरण से समाविष्ट समिति का अनुमोदन और अनुमोदन जारी करने का आधार होगा।

2. उत्सर्जन मान (नामज) और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय :

2.1 मानक -

2.1.1 इकाई के किसी प्रक्रिया उपकरण से 3 मीटर और 10 मीटर के बीच मापे गए स्थगित विविक्त पदार्थ प्रति घन मीटर 600 माईक्रोग्राम से अधिक नहीं होंगे।

2.1.2 नियन्त्रित विविक्त के साथ-साथ समूह में स्थित इकाई से 40 मीटर की दूरी पर स्थगित विविक्त पदार्थ अंशदान मूल्य 600 माईक्रोग्राम/एनएम 3 में कम नहीं होगा। मानक कार्य वर्ष में समस्त 12 महीनों के लिए महीने में कम से कम दो बार किया जाएगा।

2.1.3 स्थल की सीमा से बाहर 1 मीटर पर ध्वनि स्तर 55 डी बी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए।

2.2 प्रदूषण नियन्त्रण उपाय।

2.2.1 प्रत्येक इकाई पर्याप्त धूल-प्रतिरोधन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बाड़े सहित वायु रोधी दीवार का उपबन्ध करेगी।

2.2.2 प्रत्येक इकाई में जल-फुहार और छिड़काव प्रणाली के साथ धूल रोधी उन्मूलन प्रणाली भी होगी।

2.2.3 प्रत्येक इकाई में कण और टॉमफर बिन्दुओं पर धूल निस्सारण और संग्रहण प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी।

2.2.4 प्रत्येक इकाई में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों को चलाने के लिए पर्याप्त जलापूर्ति के साथ-साथ कम से कम दो दिनों तक का जल-भण्डार सुविधा होनी चाहिए।

- 2.2.5 प्रांगण को नियमित रूप से साफ करने और आदर करने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी ।
- 2.2.6 परिसर के भीतर और सीमा के साथ हरित पट्टी विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रजातियों के वृक्ष लगाने होंगे ।
- 2.2.7 प्रत्येक इकाई में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों के लिए, जहाँ भी उनके संचालन के लिए ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है, अनग ऊर्जा मीटर होंगे और इसका अभिलेख रखा जाएगा और हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, राज्य बोर्ड के रूप में निदिष्ट किया गया है) को इसे उपलब्ध करवाया जाएगा ।
3. स्थापित करने के लिए प्रक्रिया और राज्य बोर्ड द्वारा अनुसरण में लाई जाने वाली संक्रिया :
- 3.1.1 संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा मामले की सिफारिश करने तथा इकाई द्वारा पैरा 2.1 और 2.2 में दिए गए प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को पूरा करने के लिए सहमत होने पर ही राज्य बोर्ड सशर्त स्थापित करने के लिए सम्मति देगा ।
- 3.1.2 राज्य बोर्ड 'संचालन के लिए सम्मति' तभी देगा यदि इकाई ने स्थापित करने के लिए सम्मति में दी गई शर्तों का अनुपालन करने के लिए उपाय किए हैं ।
- 3.1.3 प्रत्येक इकाई प्रदूषण नियन्त्रण मानकों की बाबत स्व-मानिटोरिंग सुनिश्चित करेगी ।
- 3.1.4 राज्य बोर्ड इन दिशा-निर्देशों/निर्देशों में दिए गए प्रदूषण नियन्त्रण उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण होगा और राज्य बोर्ड/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 द्वारा अनुमोदित मानिटोरिक अनुसूची के अनुसार इकाई को आवश्यक मानिटोरिंग करेगा ।
- 3.1.5 प्रत्येक इकाई राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किसी अन्य निदेश का भी अनुसरण करेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-  
सचिव (वि० एवं प्रौ०) ।

[Authoritative English text of this Department Notification No. STE-E(4)-1/2003, dated 29th April, 2003 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th April, 2003

**No. STE-E(4)-1/2003.**—Whereas the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP-228/2002 titled as *Desh Raj versus State of Himachal Pradesh and Others* vide its interim order dated 3-3-2003, has directed the State Government to frame appropriate guidelines to carry out purposes and abjective of the Environment Protection Act, 1986;

And whereas it is also necessary and expedient to take immediate steps under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and rules framed thereunder

and to maintain the ecological balance in the State of Himachal Pradesh to prevent the environmental degradation and to avoid traffic and human health hazards;

And whereas the Government of India, in exercise of powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 has delegated its powers under section 5 of the said Act to the State Government *vide* notification No. S. O. 152(E) dated 10th February, 1988;

And whereas the Stone Crushing Units in the State of Himachal Pradesh are causing air pollution, traffic and human health hazards.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with Government of India. Ministry of Environment and Forests, Department of Environment. Forest and Wild Life notification No. S. O. 152(E), dated the 10th February, 1988 and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, and directions of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh issued in CWP No. 228/2002, dated 3-3-2003, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to hereby notify the following guidelines/directions for all Stone Crushing Units (hereinafter referred to as the Unit) so as to exercise greater control and vigil over the stone crushing operations to save the environment and ecology of the State with immediate effect, namely:—

## 1. Site Suitability :

### 1.1 Norms :

Taking into consideration the hill topography, availability of less land and requirement to maintain the fragile ecology of the hills, the Units shall be set-up keeping in view the following siting criteria, namely:—

Sl. No.	Criteria	Distance
1.	Minimum distance from national highway/nearest state highway	100 Mtrs.
2.	Minimum distance from the District Headquarter	1.5 Kms.
3.	Minimum distance from any Town/Notified Area Committee	1.00 Kms.
4.	Minimum distance from Village Abadi deh	250 Mtrs.
5.	Minimum distance from Hospital or Educational Institute	1.00 Kms
6.	Minimum distance from Springs, Canals, reservoirs and functional water supply schemes	100 Mtrs.
7.	Minimum distance from notified Lakes and Wetlands	500 Mtrs.

### 1.2. Notes :

- 1.2.1. All distances shall be measured as crow flies from the highest node of the crusher conveyor belt to the outer periphery of the revenue unit or the municipal limits or the periphery of the feature concerned.
- 1.2.2. In the Guidelines distances are relaxable in case of presence of any natural barrier between the site of the Unit and any of the features indicated in the guidelines.

1.2.3. In case of Shimla Town, the siting norms shall be as per the directions of the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh dated 26-7-1993 in CWP No. 51 of 1993 titled as "Court on its own motion *Versus* State of Himachal Pradesh and Others".

### 1.3. *Joint Inspection Committee for Site Appraisal :*

1.3.1. The Unit shall apply/obtain "Provisional Registration" from the Department of Industries for obtaining pre-production clearances from other Government Departments.

1.3.2. The site for setting up the Unit shall be appraised and approved by a Joint Inspection Committee consisting of the following :—

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Sub-Divisional Officer (Civil) concerned   | <i>Chairman</i>          |
| 2. Divisional Forest Officer or his representative  | <i>Member</i>            |
| 3. Representative of the Himachal Pradesh State Environment Protection and Pollution Control Board. | <i>Member</i>            |
| 4. Executive Engineer, Public Works Department or his representative.                               | <i>Member</i>            |
| 5. Executive Engineer, Irrigation and Public Health Department or his representative.               | <i>Member</i>            |
| 6. Representative of the Department of Tourism  | <i>Member</i>            |
| 7. Geologist or Mining Officer  | <i>Member-Secretary.</i> |

1.3.3. The Committee constituted in para 1.3.2. is in supersession of Industries Department Notification No. Udyog I (Chh) 4-1/85-II dated 26-4-93 and 24-12-1998. The approval of the Committee shall be basis for issue of clearance and approval including those of Himachal Pradesh State Electricity Board, Himachal Pradesh State Environment Protection and Pollution Control Board and permanent registration by the Department of Industries.

### 2. *Emission Norms and Pollution Control Measures :*

#### 2.1. *Standards :*

2.1.1. The suspended particulate matter measured between 3 meters and 10 meters from any process equipment of a Unit shall not exceed 600 micrograms per cubic meter.

2.1.2. The suspended particulate matter contribution value at a distance of 40 meters from a controlled isolation as well as from a Unit located in a cluster shall be less than 600 mg/Nm<sup>3</sup>. The measurements are to be conducted at least twice a month for all the 12 months in a year.

2.1.3. The Sound level (Leq.) at 1 meter outside the boundary of the site should not exceed 55 dB (A).

## 2.2. *Pollution Control Measures :*

- 2.2.1. Every Unit shall provide a wind breaking wal alongwith suitable enclosure to ensure adequate dust containment.
- 2.2.2. Every Unit shall have a dust suppression system with water spray and sprinkling system.
- 2.2.3. Dust extraction and collection system shall be provided at crusher and transfer points in every Unit.
- 2.2.4. Every Unit shall have adequate water supply alongwith at least two days water storage facility for running pollution control equipments.
- 2.2.5. Facility for regular cleaning and wetting of the ground shall be provided.
- 2.2.6. Trees of suitable species shall be planted to develop a green belt within and along the boundary of the premises.
- 2.2.7. Every Unit shall have separate energy meters for pollution control devices wherever the enegy is consumed for operating them and record thereof shall be maintained and made available to the Himachal Pradesh State Environment Protection and Pollution Control Board (hereinafter referred to as State Board) whenever demanded.

## 3. *Procedure for Establishment and Operation to be followed by the State Board:*

- 3.1.1. The State Board shall issue conditional "Consent to Establish" to the Unit only after the Joint Inspection Committee has recommended the case and the Unit agrees to fulfil the Pollution Control measures given in Para-2.1 and 2.2.
- 3.1.2. The State Board shall issue "Consent to Operate" only if the Unit has taken measures to comply with the conditions given in the "Consent to Establish".
- 3.1.3 Every Unit shall ensure self-monitoring with respect to pollution control standards.
- 3.1.4. The State Board shall be the authority to ensure the compliance of the pollution control measures given on these guidelines/directions and shall do the necessary monitoring of the Unit as per schedule of monitoring approved by the State Board Department of Science and Technology, Himachal Pradesh, Shimia-171002.
- 3.1.5. Every Unit shall follow any other directions issued by the State Government from time to time.

By order,

Sd/-  
Secretary .

